(ix) Increase in wages and salaries due to implementation of Engineering Award, Third Pay Commission Award and Bipartite Agreement with Crews' Union.

(x) Idleness at certain shops due to non-receipt of fresh orders, e.g. New Alipore Hull Shop, Smithy Shop, etc.

(xi) Incidence of bonus as per Bonus Act

कुतुब एक्सप्रेस को जेतवाड़ा स्टेशन पर रोका जाना

10393. **श्री सत्येन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ससद सदस्य, व्यापारी और स्थानीय लोग मध्य रेलवे में सतना और मानिकपुर के बीच जेतवाड़ा स्टेशन पर कुतुब एक्सप्रेस रोकने की व्यवस्था करने की माग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हा, तो मत्रालय के निर्णय के बावजूद वहां पर कुतुब एक्सप्रेस न रोके जाने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या रेलवे को जेतवाड़ा स्टेशन पर मेहर स्टेशन की अपेक्षा अधिक आय होती है जहा पर कुतुब एक्सप्रेस रुकती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हा ।

(ख) कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस को जैतवार स्टेशन पर ठहराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विनिश्चय नही किया गया है । कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस को जैतवार में ठहराने के लिए यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नही है ।

(ग) यात्रियों से होने वाली आमदनी जैतवार की अपेक्षा मैहर स्टेशन पर अधिक है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा के रूप में हिन्दी

10394. **श्री बलवन्त सिंह परस्ते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जो हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के साथ परामर्श कर रहे हैं ;

(ख) ये परामर्श कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में हिन्दी को लागू करने के लिए सही प्रक्रिया क्या है और विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कितना समय लगेगा ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) . हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए सयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीकारात्मक निर्णय की आवश्यकता होगी । हिन्दी को इस प्रकार की मान्यता दिलाने के सम्बन्ध मे सकल्प तभी पेश किया जा सकता है जबकि इसके आम सहमति से पारित हो जाने की या इसे बहुमत प्राप्त हो जाने की काफी अच्छी संभावना हो । किसी विशिष्ट काम पर किस अधिकारी को लगाया गया और उसका पदनाम क्या है, यह बताने की प्रथा भारत सरकार मे आमतौर से नही है ।

मोटा इलैक्ट्रीसिटी लिमिटेड, भिवानी द्वारा अदा की गई भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की खराबियां

10395. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स मोटा इलैक्ट्रीसिटी लिमिटेड, भिवानी (हरियाणा) द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी धन राशि जमा कराई गई और कितनी अभी बकाया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियो ने सूचित किया है कि मैसर्स मोटा इलेक्ट्रीसिटी लिमिटेड, भिवानी, हरियाणा नामक कोई प्रतिष्ठान नही है । तथापि, मैसर्स मोहटा इलैक्ट्रोस्टील लिमिटेड, भिवानी, हरियाणा नामक एक प्रतिष्ठान है, जिसने 31 मार्च, 1979 तक भविष्य निधि अंशदानो के रूप में 1,13,025.00 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया है । उपर्युक्त प्रतिष्ठान की ओर उक्त तारीख तक भविष्य निधि की कोई राशि बकाया नही थी ।

कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कारखाना (मैसर्स मोहटा इलैक्ट्रो-स्टील लिमिटेड) ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के लाभकारी उपबन्धो को लागू नहीं किया गया है । इस कारखाने को गलती से पहली सितम्बर, 1975 से अधिनियम के अधीन समझा गया, परन्तु तदनन्तर 28 फरवरी, 1976 से इसे अधिनियम की परिधि से निकाल दिया गया । अधिनियम की परिधि में रहने की अवधि के दौरान, 13,217.65 रुपए की धन-राशि का अंशदानों के रूप में भुगतान किया गया ।